

سری محمد شفیع قریشی۔ جس شخص نے پوسٹر لکایا ہے اس کو اپنی رائے جو ہو اس کو اظہار کرنے کا پورا پورا حق ہے لیکن ملک اور قوم کے مفاد میں جو بات عام ہے۔ وحشی ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کے یہاں براڈ گیج بھی ہے میٹر گیج بھی ہے۔ ماننے والوں کو معلوم ہے کہ عماری کونٹریس اس بات کی ہے کہ ریلوے میں چوری نہ ہو۔ ٹرانسمیشن میں جو مال میٹر گیج سے براڈ گیج میں آتا ہے تو برا نقصان ہوتا ہے تو اصولاً اس کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ سارے ملک میں ایک سسٹم قائم کر دیا جائے اس سے لوگوں کو سہولت ہوگی دیر کم لگے گی ٹرانسمیشن کے وقت کا نقصان کم ہو جائے گا۔

†[**श्री मुहम्मद शफी कुरेशी :** जिस शख्स ने पोस्टर लगाया है उसको अपनी राय जो हो उसको इजहार करने का पूरा पूरा हक है लेकिन मुल्क और कौम के मफाद में जो बात हमने सोची है, वह हम करने जा रहे हैं। आपके यहां ब्राड गेज भी है मीटर गेज भी है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि हमारी कोशिश इस बात की है कि रेलवे में चोरी न हो। ट्रांसमिशन में जो माल मीटर गेज से ब्राड गेज में आता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उसूलन इसको भी तस्लीम कर लिया गया है कि सारे मुल्क में एक सिस्टम कायम कर दिया जाये। इससे लोगों को सुविधा होगी, देर कम लगेगी, ट्रांसमिशन के वक्त का नुकसान कम होगा।]

†[] Hindi transliteration.

हरिजन बस्तियों में बिजली की व्यवस्था

*278 श्री ओउम् प्रकाश त्यागी :

श्री मान सिंह वर्मा :

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा :†

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :

श्री रत्तन लाल जैन :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की स्वतंत्रता के २५ वें वर्ष में कितनी हरिजन बस्तियों में बिजली की व्यवस्था की गयी है और कितनी हरिजन बस्तियों में बिजली की व्यवस्था अभी की जानी है ; और (ख) कब तक शेष बस्तियों में बिजली की व्यवस्था कर दी जायेगी ?

{[PROVISION OF ELECTRICITY IN HARIJAN COLONIES.

*278. SHRI O. P. TYAGI:

SHRI MAN SINGH VARMA:

SHRI V. K. SAKHALECHA :† SHRI

I. P. YADAV: SHRI RATTAN

LAL JAIN:

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state :

(a) the number of Harijan colonies which have been provided with electricity (during the 25th Anniversary of India's Independence and the number of such Harijan colonies which are yet to be provided with electricity; and

(b) the time by when the rest of the colonies will be provided with electricity?]

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI BAIJ NATH KUREEL: fa) and fb), A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) and (b) During the Silver Jubilee year of India's Independence it has been

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri V. K. Sakhalecha.

[] English translation.

suggested to the various State Governments that they should programme to electrify at least one Harijan Basti a day in their State. So far about 2,900 Harijan Bastis have been electrified since 15th August, 1972. It is estimated that in villages already electrified there may be about 36,000 adjacent Harijan Bastis which are not electrified. A scheme has been introduced last year to provide electricity to Harijan Bastis adjacent to villages already electrified and it is proposed to cover 20,000 such Bastis during the Fourth Plan. Electrification of all the Bastis in the country is linked with the progress of rural electrification which is dependant upon the Outlays provided in the Fifth and Subsequent Plans.

† [सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) भारत की स्वतंत्रता की रजत जयन्ती के वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में कम से कम एक बस्ती प्रतिदिन के हिसाब से विद्युतीकृत करने का कार्यक्रम बनाएं। अभी तक १५ आगस्त, १९७२ से २६०० हरिजन बस्तियां विद्युतीकृत हो चुकी हैं। अनुमान है जिन ग्रामों में बिजली लगाई जा चुकी है उनमें लगभग ३६,००० ऐसी सहवर्ती हरिजन बस्तियां हैं जहां बिजली नहीं दी गई। इन ग्रामों, जहां बिजली दी जा चुकी है, के साथ लगी हरिजन बस्तियों को बिजली देने की एक स्कीम पिछले वर्ष चालू की गई है और चतुर्थ योजना के दौरान ऐसी २०,००० बस्तियों को बिजली देने का प्रस्ताव है। देश में सभी बस्तियों के विद्युतीकरण का प्रश्न ग्राम विद्युतीकरण की प्रगति के साथ जुड़ा हुआ है जो कि पांचवीं

तथा इसके बाद की योजनाओं में व्यवस्थित परिणामों पर निर्भर करता है।]

श्री वीरेन्द्र कुमार सखलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे सारे देश के लगभग सभी स्टेट्स में सामान्य स्थिति यह है कि हरिजन बस्तियों में एक तो उन के छोटे मकान हैं, वहां पर सड़कों की या पानी आदि की कोई सुविधा नहीं है और इस के अलावा बिजली आदि का भी कोई इंतजाम न होने के कारण उन लोगों को वहां अत्यंत कष्ट में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। तो विशेषकर हरिजन बस्तियों में बिजली लग सके प्रत्येक स्टेट में क्या भारत सरकार इस के लिए कुछ विशेष प्रयत्न करने जा रही है?

श्री बैजनाथ कुरील : जैसा की माननीय सदस्य ने बताया, इसमें कोई शक नहीं कि जिन गांवों में विद्युतीकरण हुआ है, उन गांवों में जो हरिजन बस्तियां हैं वह अक्सर छोड़ दी जाती रहीं। यह बात अच्छी नहीं थी परन्तु ऐसा देखा गया। इसी बात को महेंजर रखकर गवर्नमेंट ने पिछले साल एक डिजीजन लिया कि जो हमारा रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्यक्रम है, उसके अन्तर्गत जिन गांवों को बिजली दी जाएगी उनमें इन बस्तियों को भी शामिल करना लाजिमी होगा और इसीलिए अब भविष्य में जितनी भी योजनाएं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन में आयेंगी उनमें इनका समावेश होना आवश्यक है। परन्तु यह हुआ कि जिन गांवों में अब तक इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, उनका क्या होगा? तो इस के लिए केन्द्रीय सरकार ने ५ करोड़ रुपये अलग से रखा है कि जिन गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है और उन गांवों में हरिजन बस्तियां रह गई हैं, हैमलेट्स रह गये हैं, उनमें विद्युतीकरण

† [] Hindi translation.

किया जाए। तो यह कार्यक्रम, यह योजना बनाई गई है, इसको हमारी रजत जयन्ती वर्ष में तेजी से चलाने का प्रावधान हुआ है।

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा : माननीय मंत्री महोदय ने जैसा बताया कि ५ करोड़ रुपया अपने केवल जहां विद्युतीकरण हो चुका है और हरिजन बस्तियों में नहीं हुआ, उन के लिए प्रावधान किया है, तो यह ऐसाउन्ट तो बहुत कम है। देश के अन्दर ७ लाख गांव हैं और अनेक गांवों के अन्दर इस प्रकार की स्थिति है कि जो हरिजन बस्तियां हैं उनमें बिजली की व्यवस्था नहीं की जाती। आगे जब रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के अन्दर गांवों में बिजली आ जाएगी, तो इसके बारे में विशेष इंतजाम करें क्योंकि ऐसे कार्यक्रम गांव पंचायतों करती है तो विशेष रूप से गांव पंचायत बिजली को इन बस्तियों तक ले जाए, इसके लिए अनुदान की व्यवस्था निश्चित तौर पर की जाए। क्या केन्द्रीय सरकार ने यह तय किया है कि जो कार्यक्रम गांव पंचायतें बनायेंगे, विद्युतीकरण करायेंगी वह हरिजन बस्तियों में भी विद्युतीकरण की व्यवस्था करे, उसके लिए उनको सहायता दी जाए, क्योंकि ५ करोड़ की राशि बहुत कम है? इस बारे में आगामी क्या योजना है, यह बताने की कृपा करेंगे?

श्री बंजनाथ कुरील : यह जो ५ करोड़ की धनराशि है, यह तो फोर्थ प्लान के लिए है, यह एक डेढ़ साल के लिए रखी गई है। लेकिन जैसा मैंने बताया, भविष्य में हेमलेट्स को, हरिजन बस्तियों की पूरी स्कीम में शामिल करना है। अभी तक जो हिसाब लगाया गया है, करीब ३६ हजार गांवों में हेमलेट्स बाकी रह गई है। यह जो स्कीम है, इसमें २० हजार गांव हो जायेंगे

तो थोड़े से बाकी रह जायेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि ५ करोड़ रुपया कम है, लेकिन यह उनहीं बस्तियों के लिए है जहां विद्युतीकरण हो चुका है और हेमलेट्स रह गई हैं और यह कार्यक्रम चौबी पंचवर्षीय योजना का है।

श्री बीरेन्द्र कुमार सखलेचा : इलेक्ट्रिफिकेशन जिनका होता है, उनके बारे में जवाब नहीं दिया।

SHRI G. A. APPAN: It is reported in the reply that is laid on the table of the House that during the Silver Jubilee year of India's Independence, it has been suggested to various State Governments that they should programme to electrify at least one Harijan Basti a day in their States and so far about 2,900 Harijan Bastis have been electrified since August 1972. It is also reported here that there are 36,000 Harijan Bastis which are not yet electrified. There are at (east 20 States in India and at (he rate of one Basti a day, it comes to 365 X 20 X 5 for the whole five year period. At this rate it is possible to electrify 36,000 Bastis. I doubt whether the Government's intention is honest or it is simply a lip-service. This is what I could gather from the way things have been going on. Even before our very eyes in this great city of Delhi a number of Harijan Bastis and Juggies are not electrified. If that is the case, how can you achieve this target? Sir, more than electricity, what about drinking water. That is not available in this city. May I know from the hon. Minister as to whether he will take up this programme of electrification in Harijan Bastis and fix a target for every month and lay a statement showing progress on the table of the House every month? And, Sir, I would like to know whether he will make a review of the progress made by them in carrying out their intentions.

DR. K. L. RAO: Sir, since 15th August 1972, we are electrifying at the rate of one thousand Harijan bastis every month and so far we have done 2,900 or 3,000 and our programme is to cover 20,000 in the Fourth Plan period and the balance

in the early years of the Fifth Plan. Necessary funds have been provided for this. For 20,000 villages we require about Rs. 5 crores and for the balance another Rs. 5 crores will be required and there will be no need for any feeling that this will not be done. The programme is well on the way and I am sure it will be completed according to schedule.

SHRI SANDA NARAYANAPPA: Sir, there is already power shortage in the country and the Government is also imposing restrictions on the use of electricity by the industrial and agricultural sectors. I want to know from the honourable Minister whether, in view of this, the Government is considering allotting Rs. 5 crores and whether they are going to carry out this programme of electrifying these Hari-jan bastis as soon as possible. I also want to know from the honourable Minister what their programme is in this regard and whether they would be able to carry it out.

DR. K. L. RAO: Electrification of Harijan bastis means only providing street lights and providing lights in schools and some such common places and I would say, Sir, without any hesitation that if it comes to cutting off supply to industries in preference to cutting off supply to the Harijan bastis; I would rather put off supply to the industries rather than doing anything to the Harijan bastis. I should say, therefore, that this programme in respect of the Harijan bastis must proceed irrespective of any other consideration.

श्री एन० एच० कुम्भारे : यह कहा गया है कि जब गांव का विद्युतीकरण किया गया तो हरिजन बस्ती को छोड़ दिया गया, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि कौन सा कारण था जिसकी वजह से कि गांव में जिस बस्ती को आप हरिजन बस्ती कहते हैं उसको छोड़ दिया गया। और एक और सवाल करना चाहूंगा कि क्या यह जरूरी है कि हरिजन बस्ती को अलग से किया जाय, उसका विद्युतीकरण अलग से किया जाय। क्यों न इस तरह के आदेश दिये जाय कि जहां पर भी विद्युतीकरण होता है तो

पूरे गांव का किया जाय और एक बस्ती को छोड़ न दिया जाय। अलग से एक बस्ती के विद्युतीकरण की आवश्यकता क्या है।

[MR. CHAIRMAN in the Chair]

DR. K. L. RAO: This is exactly what my honourable colleague had said that hereafter no village should be electrified unless it also includes a Harijan basti. So far as the previous things are concerned, out of 1,28,000 to be electrified, we find that 36,000 have not been electrified and the reason for this is the neglect by all of us, yourself and myself.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: Sir, it is our common experience that levelling up is not possible and, therefore, the Congress Government has resorted to levelling down. Is it the reason why there has been no electric supply in many of the quarters of the Members of Parliament since last evening and also in the Secretary's House?

DR. K. L. RAO: Sir, the honourable Member has referred to the temporary failure that has occurred. In this connection, I would like to read out the message that I have just now received:

"All the HT sub-stations were manned by the officers of the NDMC. No HT lines were affected. The striking workers had removed the fuse-holders on a number of LT lines and, therefore, the distribution system was affected. The areas affected were North Avenue, Bengali Market, Feroz Shah Road, Gole Market and some other areas."

Probably, the strikers wanted to draw the attention of the Members and that was why they cut off supply to the houses of the honourable Members. They have gone on strike. They have not even given notice of strike and I know nothing about it. All of a sudden this has happened in the dark hours. I hope that the honourable Members would take it seriously and see that people who do such things are dealt with seriously.

MR. CHAIRMAN: Yes, Dr. Bhai Mahavir, you want to put a question?

...All right.

DR. BHAI MAHAVIR: Sir, the statement has made a very curious and damaging admission and the honourable Minister has tried to make us partners in the blame for it by saying that everybody is responsible for it. What is the duration of the period during which these 26,000 villages have been electrified, without giving the same benefit to the Harijan bastis adjoining those villages? The question is how long it was going on. When was it that the Government of India discovered this type of practice being followed in various States? What was done to stop it just there and then? This is the type of discrimination, I presume, which is against the provisions of the Constitution.

DR. K. L. RAO: I have already given the figures. About 1,28,000 villages have been electrified but a number of Harijan bastis attached to these villages have not been electrified, and that is what we are trying to do. That is one thing. There is another point here. This electrification is done only on a certain basis. A certain criterion is fixed, and unless a certain return is there, they will not electrify the village. They were treating Harijan bastis separately. They fixed a sum of Rs. 240 for six lights. Normally, no Harijan basti can pay that much. This difficulty was there. Now we have said that the whole scheme must be taken together. The scheme should be taken as a whole, and there must be a suitable return. That is how we are trying to solve the problem.

DR. BHAI MAHAVIR: Since when this discrimination has been started?

DR. K. L. RAO: Electrification of villages has been done during the last 10 years. A number of villages have been electrified. We found out a year and half ago. that some attached Harijan bastis were left out.

*279. *The questioner (Shri Kalyan Roy) was absent. For answer vide Col. 36 infra.*

3—5 RSSND/72

*280. SHRI KRISHAN KANT†
FUEL OIL PRODUCTION

SHRI V. B. RAJU:
SHRI CHANDRA SHEKHAR:
SHRI BRAHMANANDA
PANDA:
SHRI GURMUKH SINGH
MUSAFIR:
SHRI .I. S. TILAK:

Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS be pleased to state:

fa) the annual demand and production of fuel oil since 1969 in the country and in which of these years India was surplus in fuel-oil; and

(b) whether there has been a shift from coal to fuel-oil during the last decade?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE):

(a) A statement is laid on the Table of the Sabha.

(b) To relieve the fuel shortage which developed in the southern and western parts of the country due to inadequate capacity for moving coal in the early years of the 1960s, the Government encouraged a number of industries such as cement to shift to oil and also offered freight concessions. When the transport of coal improved these concessions were withdrawn and higher excise duty was imposed on fuel oil to encourage the shift back to coal. This has had the desired results.

The demand for fuel oil has risen steadily on account of the growth of the economy and in many cases due to technological advantages of oil over coal. The Government is keeping the matter under review to discourage the use of fuel oil except in cases where its use is unavoidable on technical grounds.

STATEMENT			
Qty. in million tonnes			
Year	Fuel Oil		
	indigenous Production	Consumption	(+) Surplus (—) Deficit
1969	4.26	4.43	(—) 0.17
1970	4.24	4.65	(—) 0.41
1971	4.10	4.97	(—) 0.87

†The question was actually asked on the floor of the house by Shri Krishan Kant.